श्री नित्यानन्द राय: सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। भविष्य के लिए केन्द्र सरकार ने 80 प्रतिशत राशि, उनके पास equipments की पूरी उपलब्धता हो, इसके लिए बढ़ायी है। यह बहुत बड़ी राशि है, जो 61 हज़ार 222 करोड़ कर दी गयी है।

MR. CHAIRMAN: Q.No.126 Shri Nadimul Haque, not present. Are there any supplementaries?

Establishing new central forensic laboratories

*126. SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has set up new central forensic laboratories in the country during the last three years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of funds allocated, released and utilised in the upgradation of existing central forensic laboratories and for establishing new laboratories in the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During the last three years, the Ministry of Home Affairs has completed the construction of new buildings for Central Forensic Science Laboratories (CFSLs) at Bhopal and Guwahati. These CFSLs have become operational in their new buildings. Further, substantial work has been completed for the construction of a new building for CFSL at Pune.

(c) Details of capital funds allocated/ released and funds utilized for upgradation of existing CFSLs and establishment of new CFSLs in last three years is as below:–

(₹ in crore)

Year	Funds allocated/released	Funds utilized
2016-17	15.56	14.09
2017-18	31.16	29.61
2018-19	32.85	29.58

Further, an expenditure of ₹ 8.39 crore has been incurred under the Nirbhaya Fund in the FY 2018-19 for setting up of a state-of-the-art DNA analysis laboratory at Chandigarh.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, given the fact that the crime against women is on an alarming rise, does the Government have any plan, in the near future, of setting up more state-of-the-art DNA analysis laboratories, like, the one in Chandigarh, for instant response to references?

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, investigation के बाद criminals को the punishment should be given as fast as possible. Victims must get justice quickly. इस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने-अपने लेवल पर सेंटर्स बनाए हैं - CFSL सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और FSL स्टेट का होता है। इसके तीन existing सेंटर्स हैं, एक चंडीगढ़ में है, एक हैदराबाद, तेलंगाना में है और एक कोलकाता, West Bengal में है। इन तीनों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसके साथ-साथ महाराष्ट्र में एक नया सेंटर पूना में बना रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भोपाल में एक नया सेंटर बना है, जिसका उद्घाटन हो गया है। असम में भी गुवाहाटी में सेंटर बनाया गया है। महोदय, एक state of art के बिल्डिंग बनायी गयी है, जिसका सेंटर भी बनाया है और international standards पर हमने FSLs को बनाया है। These laboratories will house the facilities of crime case examination by using modern investigation techniques such as DNA finger printing, forensic engineering, forensic electronics, cyber mobile forensics, biology, physics, forensic intelligence, chemistry explosives, narcotics इस प्रकार अलग-अलग issues पर investigations होती हैं। महोदय, चंडीगढ़ के बारे में बात की गयी है। चंडीगढ़ में भी हमने बहुत बढ़िया सेंटर बनाया है। चंडीगढ़ में existing CFSL moderation with state-of-the-art DNA Analysis Centre हमने बनाया है, उसके लिए हमने पैसे खर्च किए हैं। इस आधार पर देश में अलग-अलग जगह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सेंटर्स हैं, हम केन्द्र सरकार से उन्हें पैसे देते हैं। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी नए सेंटर्स बना रही है।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, whether any more such...

MR. CHAIRMAN: He has already named four centres.

श्री राम नाथ ठाकुर: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नए वित्तीय वर्ष में बिहार में कितनी प्रयोगशालाएं बनाने का विचार रखते हैं?

MR. CHAIRMAN: Is there a proposal to set up new laboratories in Bihar?

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, कोलकाता में जो सेंटर हम बना रहे हैं, वह बिहार का catchment area होता है। जो कोलकाता का सेंटर बनाया है, वह ज़ोनल सेंटर है, जिसमें ओडिशा, बिहार, झारखंड, वैस्ट बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसके साथ-साथ बिहार के लिए भी हम अलग से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। हम बिहार में भी यूनिट बना रहे हैं और वहां के लिए भी पैसे दे रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह मन्हास: सभापति जी, जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और वहां से investigation के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। तथा रिपोर्ट वापस आने तक कुछ पता ही नहीं लगता है। तो क्या जम्मू-कश्मीर में इस प्रकार की प्रयोगशाला प्रारम्भ हो सकती है?

श्री जी. किशन रेड्डी: सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर का सेंटर अलग नहीं है। चंडीगढ़ में ज़ोनल सेंटर है। चंडीगढ़ के अंदर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का सेंटर है। उसमें Central Government की जितनी भी investigations होती हैं, वे चंडीगढ़ में होती हैं।

श्री सभापति: यह अच्छा हो गया कि युवा राज्य मंत्री को केबिनेट मंत्री जी ने प्रश्नों का समाधान देने के लिए मौका दिया है। इसलिए उनका अभिनन्दन करना चाहिए।

Revival of Air India

*127. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government has any intention to revive Air India after the disinvestment initiative did not receive proper response from the interested parties;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the revival package shall have the package of clearing the debt of over ₹ 55,000 crore in the event of revival; and

(d) what measures the proposal is likely to have to avoid recurrence of similar situation in future?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government is committed to the disinvestment of Air India. In this regard, the Government prepared a revival plan of Air India.

(b) The Government prepared the revival plan to bring operational and financial efficiency in Air India to effectively prepare it for disinvestment. Air India's Revival Plan is focused on building a competitive and profitable airline group. The Revival Plan comprises several major elements including, *inter-alia*:

(i) A comprehensive financial package, as approved by Government of India which also includes transferring of debt and non-core assets to Special Purpose Vehicle (SPV);